भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 897

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राजस्थान में स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

897. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए किसी विशेष योजना पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और राज्य के झुंझुनू जिले सहित जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में चिकित्सकों और नर्सों की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में एम्स जैसे नए संस्थान स्थापित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से अल्पसेवित और हाशिए पर रह रहे समूहों के लिए गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है। यह मंत्रालय एनएचएम के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) का उद्देश्य 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उप-स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के लिए अवसंरचना विकास, ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों, एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और

क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों के लिए सहायता का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान राज्य के लिए पीएम-एबीएचआईएम के तहत 2,666.48 करोड़ रुपये की कुल राशि अनुमोदित की गई है।

पंद्रहवें-वित्त आयोग ने राज्यों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से पंचवर्षीय अवधि (2021-2026) में कुल 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। राजस्थान राज्य के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पंद्रहवें-वित्त आयोग स्वास्थ्य अनुदान के तहत 4,423.06 करोड़ रुपये की कुल राशि अनुमोदित की गई है।

दिनांक 31.01.2025 तक की स्थिति के अनुसार, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (सीपीएचसी) प्रदान करने के लिए मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) का उन्नयन करके, जिसमें निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं और जो सार्वभौमिक, नि:शुल्क और समुदाय के निकट हैं, कुल 1,76,325 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) को संचालित किया गया है।

(ग): भारत सरकार ने देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदायगी को प्रोत्साहित करने के लिए चिकित्सा पेशेवरो को प्रोत्साहन और मानदेय देने के रूप में अनेक पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त चिकित्सकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता देना ताकि वे ऐसे क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सेवाएं देने को आकर्षक समझें।
ii. ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन करने हेतु विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों / प्रशिक्षित आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (ईएमओसी), बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट / लाइफ सेविंग एनेस्थीसिया स्किल्स (एलएसएएस) वाले प्रशिक्षित चिकित्सकों को मानदेय देना।
iii. चिकित्सकों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर एएनसी जांच और अभिलेखन सुनिश्चित करने के लिए एएनएम को प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहन।
iv. राज्यों को विशेषज्ञ चिकित्सकों को आकर्षित करने के लिए परस्पर सहमति से तय वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन शामिल है।
v. एनएचएम के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत स्टाफ के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
vi. विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए एनएचएम के तहत चिकित्सकों को बहु-कौशल सहायता दी जाती है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण

स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

(घ) से (च): राजस्थान राज्य के जोधपुर में एम्स की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत की गई है और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है। वर्तमान में, पीएमएसएसवाई के अंतर्गत राजस्थान (झुंझुनू जिले सहित) में दूसरे एम्स का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****